(घ) यह मानना होगा कि प्रौढ़ शिक्षा जैसे सामाजिक कार्य के कार्यक्रम के परिणामों की उपलब्धियों को, उन पर किये गये वित्तीय खर्च से नहीं मापा जा सकता । ऐसे कार्यक्रमों की सफलता काफी हद तक सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसमें अधिकतर वास्तव में प्रौढ़ शिक्षु रहते तथा कार्य करते हैं। इसके अलावा वर्ष 1987–90 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:–

(i) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रथम दो वर्ष साक्षरता के लिये सकारात्मक वातावरण पैदा करने, इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिये योजनाओं में संशोधन करने, विभिन्न स्तरों पर मिशन का प्रबंध ढांचा तैयार करने, अच्छी विश्वस्नीय तथा स्वैच्छिक एजेंसियों का पता लगाने तथा सभी संबंधितों से गहन परामर्श करने आदि में व्यतीत हो गये।

(ii) गोवा, केरल राज्यों तथा संघशासित प्रदेश पांडिचेरी में संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिये जन-अभियानों को शुरू करने से इन राज्यों/संघशासित प्रदेशों में सभी केन्द्र-आधारित कार्यक्रम रूक गये । इन अभियानों की वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी केवल वर्ष 1990–91 में ही हुई अतः इन उपलब्धियों को वर्ष 1989–90 में दर्शाया नहीं जा सका।

(iii) मई, 1988 में शुरू किये गये राष्ट्रीय मिशन साक्षरता के पश्चात् जिन विभिन्न योजनाओं में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई थी ने भी इस केन्द्र आधारित कार्यक्रमों को आगे उसी रूप में जैसा कि रा0 सा0 मि0 से पूर्व थे जारी रखने के बारे में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

कमजोर वर्गों में शिक्षा का प्रसार

श्री राम जेठमलानी :
श्री रणजीत सिंह :

926. क्या मानव विकास संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समिति के एक दल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में समाज के लिये कमजोर वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिये सरकार द्वारा एक योजना शुरू किये जाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी कार्यदल ने दिनांक 5–6 मई, 1992 को हुई अपनी बैठक में सुविधाहीन वर्गों के लिये कोई शैक्षिक कार्यक्रमों की सिफारिशें की हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधन के अनुसरण में कार्रवाई कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है।

Universities in the Country

927. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU; Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of State Universities/Central Universities) Deemed Universities opened during the last two years and proposed to be opened in the near future with their names;

(b) what has been the enrolment perenctage in the faculties of Arts, Commerce and Science at the first degree level during the same period, proposed allocation for the current

year and details of the five Universities having highest enrolment of students;

(c) whether Government nave decided to bifurcate the Commerce faculty at the first degree level and start enrolment for Chartered Accountants or Company Secretary's courses, with detailed programme in this context; and

(d) whether Government have received demands and are contemplating to declare Utkal University as a Central University?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) According to the information furnished by U.G.C, the following State Universities have been established during the last two years:

Name of University	Year of establishmen
(1) Yashwant Rao Chavan Open Univerity, Nasik .	1990
(2) Tamilnadu Veternary & Animal Science University, Madras	1990
(3) North Maharashtra University, Jalgaon	1991
(4) Nalanda Open University, Nalanda	1991
(5) Manonmaniam Sunderaar University, Tirunalveli	1991
(6) Chitrakot Gramodaya Vishvidyalaya, Chitrakot, Distt. Satna	1991

The Deccan College Post-graduate and Research Institute, Poona; Jain Visva Bharati Institute, Ladnun (Rajasthan) and the Bengal Engineering College, Sivpur and Forest Research Institute, Dehradun were notified as Deemed to be Universities.

The legislation has been enacted to establish Central Universities at Silchar in Assam and at Lumami in Naga land, It has also been agreed, in principle, to establish a second Central University in Assam

(b) The enrolment of students in faculties of Arts, Commerce and Science is 39.5 per cent, 19.5 per cent and 22.8 per cent respectively. According to the information furnished by the UGC, the Commision has not allocated any targets of enrolment between different faculties.

(c) According to the information furnished by UGC, the Commission has no proposal under consideration for bifurcating the Commerce faculty at the first degree level.

(d) Yes, Sir Utkal University has been established under an Act of State Legislature of Orissa and, as a matter of policy, the Central Government do not convert State Universities into Central Universities. ,

Funds for vocational education to Madhya Pradesh

928. SHRI GHUFRAN AZAM; Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government in order to promote vocational education in the country has allocated special funds to the States and Union Territories during the current financial year;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the details of the funds allocated to the Madhya Pra desh for this purpose;